डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 जून, 2021, डिस्पेच दिनांक 16 जून, 2021

| वर्ष 65 | अंक 2 | भोपाल | 16 जून, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

कोविड महासंकट में अनाथ हुए बच्चे यह न समझें कि उनके माँ-बाप नहीं हैं : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 173 बच्चों को पेंशन वितरित

राज्य सरकार हर कदम पर बच्चों के साथ है ● मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना आरंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम कोविड के महासंकट में अनाथ हुए बच्चों को यह अहसास नहीं होनें देगें कि उनके माँ–बाप नहीं हैं। हम हर बच्चे की उंगली थामेंगे। कोरोना की विपदा के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भोजन और आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। बच्चे मेहनत करें, अपने माता–पिता के सपनों को साकार करें। मैं आपका मामा और कल्याणकारी राज्य सरकार हर कदम पर आपके साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल सेवा योजना के पात्र हितग्राही बच्चों को निवास से वर्चुअली पेंशन राशि का वितरण किया। योजना के शुभारंभ अवसर पर 130 परिवारों के 173 बच्चों के खातों में प्रति बच्चा प्रतिमाह 5 हजार रूपये के मान से सिंगल क्लिक से राशि अंतरित की गई। प्रमुख

सचिव महिला एवं बाल विकास श्री अशोक शाह ने योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना के हितग्राही बच्चों और बच्चों के संरक्षकों से वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अभिभावकों और बच्चों को संबोधित भी किया। प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यक्रम से जुड़ी थीं।

प्रभावित बच्चों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए है योजना

उल्लेखनीय है कि कोरोना के कारण जिन बच्चों के सिर से माता–पिता का साया उठ गया है उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और उनके गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह के लिए मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल सेवा योजना आरंभ की गई है। 21 मई 2021 से आरंभ इस योजना में बच्चों को 5 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, निःशुल्क राशन और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

मेरी जिंदगी का सब से भयानक दौर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश एक भयानक त्रासदी से गुजरा है। ऐसी महामारी सैकड़ों सालों में एक बार आती है। कोरोना की पहली लहर का प्रकोप कम था परंतु दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ी और वायरस की अधिक घातकता के कारण कई लोग हमारा साथ छोड़ गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह मेरी जिंदगी का सब से भयानक दौर था। संभालने के कई प्रयासों के बाद भी हम कई भाई–बहनों को बचा नहीं पाये। मासूम बच्चों के सिर से माता–पिता का साया उठने से स्थिति अधिक पीड़ादायक बनी। जिन घरों में अब माता–पिता दोनों नहीं हैं वहां वेदना बहुत अधिक है।

सरकार और समाज को इन बच्चों का दायित्व लेना होगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे बच्चों को दर–दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

कृषि मंत्री श्री पटेल ने किसानों के खाते में डेढ़ करोड़ से अधिक राशि की अंतरित

रायसेन और भोपाल के 214 किसान हुए लाभान्वित

भोपाल। किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने भोपाल और रायसेन के 214 किसानों के खातों में एक करोड़ 60 लाख रुपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग और दोनों जिलों के 6 किसान उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति, रायसेन में वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यतिक्रमी फर्म द्वारा क्रय कृषि उपज धान के 222 किसानों की 2 करोड़ 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान लंबित पाया गया था। उन्होंने बताया कि किसानों के अभिलेखों का परीक्षण किया जाकर पात्र पाये गये 169 किसानों के खाते में एक करोड़ 24 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई। इसी प्रकार कृषि उपज मण्डी समिति, भोपाल में भी 107 किसानों की

73.48 लाख रुपये की राशि का भुगतान लंबित पाया गया था। अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत 45 कृषकों के खाते में 36 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि रायसेन के शेष 53 कृषकों और भोपाल के 62 कृषकों के अभिलेखों के परीक्षण का कार्य जारी है। परीक्षण उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

मण्डी बोर्ड में कृषि मंत्री श्री पटेल, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने रायसेन के 4 कृषकों श्री मनमोहन पाटीदार, श्री रामगोपाल पाटीदार, श्री अभिषेक ठाकुर और श्री वीर सिंह पटेल के साथ भोपाल के 2 कृषकों श्री बनवारी लाल और श्री त्रिलोक सिंह को राशि अंतरित कर मुँह मीठा कराकर बधाई दी।

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना का आदेश जारी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार राज्य शासन ने उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित/स्थाईकर्मी/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आउटसोर्स/मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक/सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड–19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना लागू कर दी है।

सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी, जिसमें मृत सेवक नियोजित था।

पात्र कर्मी

राज्य के समस्त नियमित/स्थाईकर्मी/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक, जिनका वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त, जिनका पारिश्रमिक/मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। विधि द्वारा स्थापित आयोग, ऐसी संस्थाएँ, जिनका शत–प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इसके लिये स्थापना अनुदान दिया जाता है, उनमें कार्यरत सेवायुक्त पात्र होंगे।

पात्रता की शर्तें

मृतक सेवायुक्त मान्य चिकित्सीय जाँच में (RAT@ RTPCR) कोविड–19 पॉजिटिव पाया गया हो तथा उसकी मृत्यु उपचार के दौरान हुई हो अथवा स्वस्थ होने के बाद पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर किसी भी बीमारी से मृत्यु हो गयी हो। मृत्यु की तिथि पर वह शासन के नियोजन/शासकीय कार्य में कार्यरत हो। मृतक सेवायुक्त शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिये।

योजना में अनुकम्पा नियुक्ति के लिये परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 29 सितम्बर, 2014 की कण्डिका–2 के अनुसार होगा। मृतक शासकीय सेवक/सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने में आयु का बंधन नहीं होगा। दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो, तो वह अनुकम्पा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा। यदि किसी शासकीय सेवक/सेवायुक्त की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के दौरान होती है, तो अनुकम्पा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा। जिन परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

योजना की अवधि

योजना एक मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। अगर सेवायुक्त योजनावधि में कोविड–19 पॉजिटिव था, लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात परंतु कोविड–19 पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर हो जाती है तब भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।

अनुकम्पा नियुक्ति के पद

योजना में कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा धारित

मृतक सेवक के नियोजन का प्रकार	पात्र आश्रित के नियोजन का प्रकार
नियमित	नियमित
कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत	कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत
संविदा	संविदा
दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर/आउटसोर्स/मानदेय	आउटसोर्स

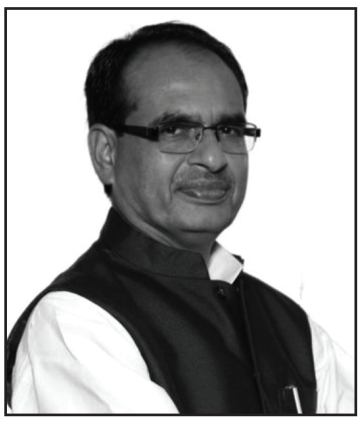

योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग–3 (गैर कार्यपालिक पद) अथवा वर्ग–4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी, जिस प्रकार के नियोजन में मृतक सेवक नियोजित था।

अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया

अनुकम्पा नियुक्ति के लिये आवेदन–पत्र उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख, जिसमें दिवंगत सेवायुक्त अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन मृत्यु दिनांक से 4 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में विलम्ब के कारणों से संतुष्ट होने पर दावा स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकारी अधिकतम तीन माह तक का विलम्ब माफ कर सकेंगे। अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे के लिये ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय/विभाग में बनाई जायेगी एवं इसका क्रम दिवंगत सेवायुक्त की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित किया जायेगा, अर्थात जो सेवायुक्त पहले दिवंगत हुआ है, उसके आश्रितों को पहले अनुकम्पा नियुक्ति आरक्षण नियमों का पालन करते हुए दी जायेगी। अनुकम्पा नियुक्ति यथासंभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जायेगी, जिसमें दिवंगत सेवायुक्त निधन के पूर्व नियोजित था। यदि विभाग की स्थापना में ऐसा पद रिक्त नहीं है, जिस पर परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है, तो इसके लिये सांख्येत्तर पद निर्मित किया जा सकेगा। ऐसे सांख्येत्तर पद पर की गई नियुक्ति भविष्य में नियमित पद की रिक्ति के विरुद्ध समायोजित की जायेगी एवं पात्र आश्रित की पदोन्नति एवं अन्य कारणों से सांख्येत्तर पद रिक्त होने पर स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सांख्येत्तर पद निर्मित करने की अनुमति शासन द्वारा गठित समिति द्वारा दी जायेगी। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। समिति में प्रमुख सचिव, वित्त और विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य सचिव होंगे।

दिवंगत सेवायुक्त के परिवार को शपथ–पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा, जिसको अनुकम्पा नियुक्ति दी जाना है। दिवंगत सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने की स्थिति में उस पात्र अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत सेवायुक्त के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण–पोषण करेगा। आउटसोर्स के रूप में पात्र आश्रित को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियोजित कराया जायेगा।

प्रकरण स्वीकृति के लिये सक्षम अधिकारी

जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बाद नियुक्ति आदेश विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

जिला कलेक्टर अनुमोदन देने से पूर्व, जिले में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुकम्पा नियुक्ति के समस्त प्रकरणों की समीक्षा करेंगे, ताकि यथासंभव संबंधित जिले में ही पात्र आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सके। यदि किसी विभाग में उपयुक्त पद रिक्त न हो, तो जिले के अन्य किसी ऐसे विभाग में पद रिक्त होने पर अनुकम्पा नियुक्ति अन्य ऐसे विभाग में दी जाने के निर्देश कलेक्टर संबंधित को दे सकेंगे। यह अनिवार्यता नहीं रहेगी कि जिले में अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाये, जिसमें मृत कर्मचारी कार्यरत था।

सचिवालय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ सेवायुक्तों के प्रकरणों में संबंधित विभाग प्रमुख सक्षम प्राधिकारी होंगे। दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर पर कार्यरत/आउससोर्स/मानदेय कर्मी की मृत्यु पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित करने के लिये कलेक्टर/सक्षम विभागीय अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी होंगे।

अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल/संस्थाओं में नियोजन

राज्य शासन के निगम/मण्डल/संस्थाओं/प्राधिकरण/विश्वविद्यालयों/स्थानीय निकाय में कार्यरत नियमित/स्थाईकर्मी/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/आउटसोर्स सेवायुक्तों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन से इस योजना के अनुरूप उसी संस्था में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। इन संस्थाओं को प्रकरण कलेक्टर को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक माह की समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन में मध्यप्रदेश को 5,117 करोड़ रुपये आवंटित किये

1185 करोड़ रुपये का अनुदान भी जारी, 2021–22 में मध्य प्रदेश को आवंटन में चार गुना वृद्धि

भोपाल। मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा 1184.860 रुपये की पहली खेप राज्य को जारी की गई है। वर्ष 2021–22 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को 5,116.790 करोड़ रुपये की सहायता आवंटित की गई है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में शामिल थे। श्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ दो दौर की विस्तृत समीक्षा बैठक की।

कोरोना नियंत्रण में है, अब आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए जुटना होगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 2023 तक प्राप्त किये जाएँ ● मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप पर अधिकारियों को किया संबोधित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड के विरुद्ध युद्ध के साथ–साथ आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करना होगा। कोविड के विरूद्ध लड़ाई जारी रहेगी पर दूसरी गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करना है। कोरोना संक्रमण के कारण राजस्व और विकास के कार्य प्रभावित हुए हैं, परंतु उपार्जन, मनरेगा और तेंदूपत्ता तुड़ाई का काम निर्बाध रूप से जारी रहा। अगस्त 2020 में हमने व्यापक विचार–विमर्श कर आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप बनाकर सभी क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित किये थे। इस दिशा में हम तेजी से कार्य कर रहे थे। परंतु कोरोना की आपदा के कारण इनमें से कई कार्य धीमे पड़े या रूक गये। प्रदेश में अब कोरोना नियंत्रण में है, अतः हमें एक बार फिर तेजी से इस दिशा में कार्य आरंभ करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के मुख्य बिन्दुओं पर संबंधित अधिकारियों को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस प्रकार की गतिविधियाँ जारी रहेंगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म–निर्भर भारत के रोडमैप के चार मुख्य आधार स्तम्भ क्रमशः भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा अर्थ–व्यवस्था एवं रोजगार हैं। स्वास्थ्य के अंतर्गत कोरोना की

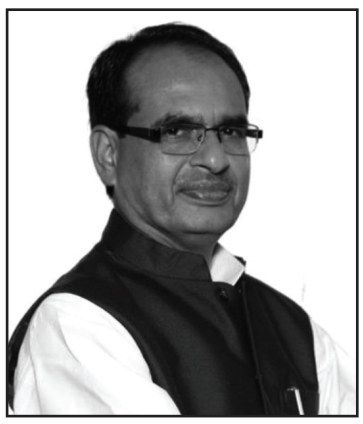

तीसरी संभावित लहर का सामना करने के उद्देश्य से डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती, ऑक्सीजन में आत्म–निर्भरता, आवश्यक अधोसंरचना विकास और उपकरणों की आपूर्ति जैसे कार्य करना है। इसके साथ ही अर्थ–व्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में भी तेजी से गतिविधियाँ बढ़ानी हैं। जब कोरोना का प्रकोप अधिक नहीं था उन दिनों लगभग 1900 एमएसएमई ईकाइयों का लोकार्पण किया गया था। रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस प्रकार की गतिविधियाँ जारी रहेंगी।

आठ मिशनों में संचालित हों गतिविधियाँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के अंतर्गत निर्धारित अधिकांश गतिविधियों की समय सीमा वर्ष 2023 है। कोरोना के कारण गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। आत्म–निर्भर भारत के अंतर्गत आठ मिशन क्रमशः मिशन अर्थ, मिशन दक्ष, मिशन जनगण, मिशन निरामय, मिशन बौधि, मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय के अंतर्गत गतिविधियाँ संचालित की जाना हैं। सभी मिशनों के अंतर्गत कार्यों को गति देते हुए इनकी मानिटरिंग आत्म–निर्भर पोर्टल के माध्यम से करना तत्काल आरंभ किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में 906 गतिविधियाँ और 3 हजार 25 उप गतिविधियाँ आरंभ की गई थीं। यह प्रसन्नता का विषय है कि 796 गतिविधियाँ अब तक पूर्ण भी हो चुकी हैं। इस दिशा में हमें पुनः उत्साह से लगातर कार्य करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि सम–सामयिक कार्यों जैसे वर्षा काल की तैयारी, सड़कों का रख–रखाव, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, उपार्जन, बोवनी की तैयारियों की निरंतर समीक्षा भी आवश्यक है।

कोरोना की चुनौती के बीच गेहूं खरीदी में होशंगाबाद फिर बना प्रदेश में अग्रणी

जिले में रिकॉर्ड खरीदी, 75 हजार 709 किसानों से खरीदा गया 8 लाख 52 हजार 724 मीट्रिक टन गेहूं

भोपाल। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला होशंगाबाद गेहूं खरीदी में प्रदेश में अग्रणी बना है। होशंगाबाद जिले में पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड खरीदी की गई है। जिले में 75 हजार 709 किसानों से 8 लाख 52 हजार 724 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई हैं। पिछले वर्ष 70 हजार 754 किसानों की तुलना में इस वर्ष 75 हजार 709 किसानों से गेहूं की खरीदी की गई हैं। कोरोना संक्रमण काल की चुनौतियों से निपटने के साथ–साथ समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदी कार्य का सफल क्रियान्वन किया गया है। खरीदी के लिए निर्धारित सभी केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी पूरी सजगता, सतर्कता और सुरक्षा बरती गई। जिला प्रशासन द्वारा बेहतर रणनीति और मैनेजमेंट से किसानों के हित में कार्य किया गया है।

खरीदी केंद्रों से गेहूं के उठाव के लिए परिवहन कर्ताओं से समन्वय कर ज्यादा से ज्यादा व्हीकल परिवहन कार्य में नियोजित किए गए। जिले में समर्थन मूल्य पर 852724 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई तथा 842618 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया गया है जो की कुल खरीदी मात्रा का 99 प्रतिशत है। साथ ही तेजी से भुगतान की कार्यवाही कर 72666 किसान भाइयों को 1566.95 करोड़ का भुगतान किया गया है, ताकि कोरोना महामारी के इस संकट किसान आर्थिक रूप से परेशान न हो।

ऐसे बने नंबर वन, यह रहे प्रमुख फैक्टर्स

कोरोना संक्रमण के संकट में किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हुए सुव्यवस्थित खरीदी के लिए कारगर रणनीति बनाई गई और उसका मैदानी स्तर पर प्रभावी इंप्लीमेंटेशन किया गया। सेंटर सिलेक्शन, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज प्लानिंग, जिला स्तरीय नोडल ऑफिसर की तैनाती, किसानों को समय पर भुगतान, माइक्रो मॉनिटरिंग सिस्टम आदि फैक्टर्स

पर विशेष काम किया गया।

गेहूं खरीदी की त्रि–स्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था

कलेक्टर श्री धनंजय सिंह द्वारा खरीदी केंद्रों पर चाक–चौबंद व्यवस्था एवं किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए त्रि–स्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाई गई है। जिसमें जिला, अनुविभाग एवं तहसील स्तर के प्रत्येक केंद्रों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा ना केवल खरीदी कार्य की सघन मॉनिटरिंग बल्कि किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया गया। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा लगातार खरीदी कार्य की नियमित माइक्रो मॉनिटरिंग एवं मौका भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

कंट्रोल रूम बना मददगार

जिले में गेहूं खरीदी के संबंध में किसानों की समस्याओं का निराकरण हेतु स्थापित कंट्रोल रूम काफी मददगार साबित हुआ। खरीदी काल के दौरान कुल 759 शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा कंट्रोल रूम से खरीदी केंद्रों पर बारदाना सहित अन्य लॉजिस्टिक्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं समीक्षा हेतु कंट्रोल रूम में नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सभी केंद्रों पर उपार्जन केंद्र प्रभारी से चर्चा कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई।

खरीदी कार्य में स्व–सहायता समूह की महिलाओं ने भी निभाई सशक्त भूमिका

जिले में पहली बार स्व–सहायता समूह की महिलाओं द्वारा भी गेहूं खरीदी कार्य में अपनी सशक्त भूमिका निभाई गई। जिले के होशंगाबाद अंतर्गत खरीदी केंद्र नीमसाड़ियां में मां गंगा एवं सोहागपुर अंतर्गत अजनेरी खरीदी केंद्र पर मां नर्मदा स्व–सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सफलतापूर्वक खरीदी कार्य किया गया। इन केंद्रों पर कुल 253 किसानों से 31141.19 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।

आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार : मंत्री श्री सिंह

भोपाल। औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों में पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने और समग्र टीकाकरण अभियान में सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। अगली लहर के लिए सतर्क रहने के लिए हमें टीकाकरण प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।

श्री दत्तीगांव मध्यप्रदेश में पीएंडजी के मंडीदीप प्लांट में शुक्रवार को ''फिक्की–पी एंड जी–अपोलो हॉस्पिटल्स कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव'' के वर्चुअल लॉन्च को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी फिर से शुरू करने के लिए कदम उठा रहे हैं और उद्योगों से आगे आने का आग्रह कर रहे हैं।

श्री दत्तीगांव ने कहा कि उद्योग पूरे चुनौतीपूर्ण कोविड समय के दौरान काम कर रहे हैं और जीरो–मेन डे लॉस सुनिश्चित

टीकाकरण हमें कोविड के लिए तैयार करेगा

कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि उद्योग समाज के लिये काम करें। उद्योग जगत को भी आगे आना चाहिए और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देना चाहिए, क्योंकि सरकार जीवन बचाने के लिए एक–एक पैसे का उपयोग कर रही है।

राज्य में टीकाकरण अभियान पर श्री दत्तीगांव ने कहा कि शुरू में चुनौतियां थीं लेकिन अब वैक्सीन की उपलब्धता के साथ अधिक लोग आगे आ रहे हैं। अधिक से अधिक उद्योगों को अपने कर्मचारियों को टीका लगाने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मैं टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ–साथ फिक्की और पीएंडजी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि इससे आस–पास के क्षेत्र के लिए भी एक सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि हम न केवल अपने लोगों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन ने कहा कि जो लोग अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और प्रशासन सहित महामारी का प्रबंधन कर रहे थे, उन्हें सबसे पहले टीका लगाया गया था। अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्र (उद्योग) के वैक्सीनेशन ड्राइव चलाकर अपने कर्मचारी, उनके परिजनों और उद्योग साझेदारों को यह संदेश दें कि वे उनकी परवाह करते हैं।

श्री मधुसूदन गोपालन, अध्यक्ष, फिक्की एफएमसीजी कमेटी और सीईओ, प्रॉक्टर एंड गैंबल इंडिया ने कहा कि– हम इस कठिन समय में अपने कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और समुदायों का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें टीकाकरण अभियान की मेजबानी करने वाली पहली कंपनियों में से एक होने पर गर्व है। हम मध्य प्रदेश में टीकाकरण के लिए 5 करोड़ रुपये का योगदान दे रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार के एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री जॉन किंग्सली ने कहा कि फिक्की–पी एंड जी–अपोलो अस्पताल राज्य में टीकाकरण अभियान को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है, और हम राज्य के विकास के लिए उद्योग के साथ संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।

फिक्की के महासचिव श्री दिलीप चेनॉय ने कहा कि जब भी देश, समाज, समुदाय को अत्यधिक समर्थन की आवश्यकता होती है, फिक्की के सदस्य हमेशा सबसे आगे रहे हैं।

ढाई एकड़ से कम जोत वाले किसानों के नाम संबल योजना में जोड़ें : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले के मसन गांव में ''मेरा गांव – मेरा तीर्थ'' अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन किसानों की ढाई एकड़ से कम जोत है, उन्हें संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित–लाभ प्रदान कर लाभान्वित किया।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मेरा गाँव –मेरा तीर्थ अभियान का मूल उद्देश्य गरीबों, किसानों की समस्या को दूर करना है। इस अभियान के माध्यम से गरीबों को प्रदेश सरकार की योजनाओं से घर बैठे लाभान्वित किया जाएगा। मसन गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 75 हितग्राहियों को आधार कार्ड, 102 हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची, 11 हितग्राहियों को मनरेगा जॉब कार्ड, 260 हितग्राहियों को पेंशन योजना, 302 हितग्राहियों को गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, 457 हितग्राहियों आयुष्मान कार्ड, 162 हितग्राहियों को तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

पंचायत भवन का किया भूमि–पूजन

मंत्री श्री पटेल ने ग्राम पंचायत भवन का भूमि–पूजन भी किया। उन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए की राशि से नवीन भवन का निर्माण होगा। साथ ही मसनगाँव नदी पर स्टॉप डेम, मसनगाँव से खमलाय ग्रेवल मार्ग 3 किलोमीटर, योगेश पाटिल के घर से सिराली रोड तक 500 मीटर ग्रेवल मार्ग, शिवनारायण मालवीय के खेत से खमलाय रोड तक 700 मीटर ग्रेवल मार्ग, कमताड़ा से मुर्गा माइनर 2 किलोमीटर ग्रेवल मार्ग, सिराली रोड से मोहन भामरे के खेत तक 1 किलोमीटर ग्रेवल मार्ग भी जल्द ही बनाए जाएंगे।

कार्यक्रम में सरपंच श्री योगेश पाटील, श्री अमर सिंह मीणा एवं स्थानीय जन–प्रतिनिधि एवं शासकीय कर्मचारी उपस्थित थे।

फसल ऋण राशि 30 जून तक किसान कर सकेंगे जमा : श्री पटेल

भोपाल। किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फसल ऋण वसूली को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 जून तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी फसल ऋण वसूली की तारीख को आगे बढ़ाया गया है।

रणनीति पूर्वक मंडियों को स्मार्ट बनाया जाएं : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि मंडियों को रणनीति पूर्वक स्मार्ट मंडियों के रूप में विकसित किया जाए। मंत्री श्री पटेल ने मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिए।

मंत्री श्री पटेल ने बैठक में मंडी में आवक की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि किसानों को लाभान्वित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे मंडियों में आवक की स्थिति बेहतर हुई है। श्री पटेल ने कहा कि इस वर्ष सरकार के द्वारा क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए चना, मसूर और सरसों का उपार्जन गेहूँ के साथ किया गया है। इससे किसानों को उपज का बेहतर लाभ प्राप्त हुआ है।

श्री पटेल ने कहा कि सरकार के फैसले से किसानों को चना, मसूर और सरसों पर समर्थन मूल्य से भी अधिक का लाभ मिला है।

बैठक में बताया गया कि विगत वर्ष 23 मार्च से अप्रैल 2020 तक और इस वर्ष भी मंडिया ज्यादातर बंद होने से आवक पर फर्क पड़ा था। इसके बावजूद मंडियों ने अच्छा काम काज किया। श्री पटेल ने कहा कि ये नीतिगत सही निर्णयों से ही सम्भव हुआ है। इससे किसानों की आय दो गुना करने का प्रधानमंत्री का सपना पूर्ण करने में सफल हुए।

बैठक में मंडी बोर्ड की एमडी सुश्री प्रियंका दास सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

शिक्षा को विद्यार्थी के लिये उपयोगी बनाने में आधुनिक तकनीक का करें प्रयोग : राज्यपाल श्रीमती पटेल

ऑनलाइन शिक्षण है भविष्य की व्यवस्था ● पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल का चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न

भोपाल। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कोविड–19 महामारी के कारण आज हमारे समक्ष अनगिनत चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसमें अवसर भी हैं। आवश्यकता, स्वमूल्यांकन, स्पष्ट कार्य योजनाओं एवं दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का निदान करते हुए छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने की है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षण भविष्य की व्यवस्था है। इसका प्रयोग शिक्षा को विद्यार्थी के लिये उपयोगी बनाने में किया जाना चाहिए। यह कार्य कक्षा के सभी छात्र–छात्राओं को एक समान मानने के बजाय उनकी रुचि, विशेषता और कमजोरियों के हिसाब से अतिरिक्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा कर किया जा सकता है। श्रीमती पटेल आज मध्यप्रदेश के पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर ''विश्वविद्यालय प्रबंधन : महामारी के परिप्रेक्ष्य में चुनौती एवं संभावनाएँ'' विषय पर संगोष्ठी को ऑनलाइन लखनऊ राजभवन से संबोधित कर रही थी।

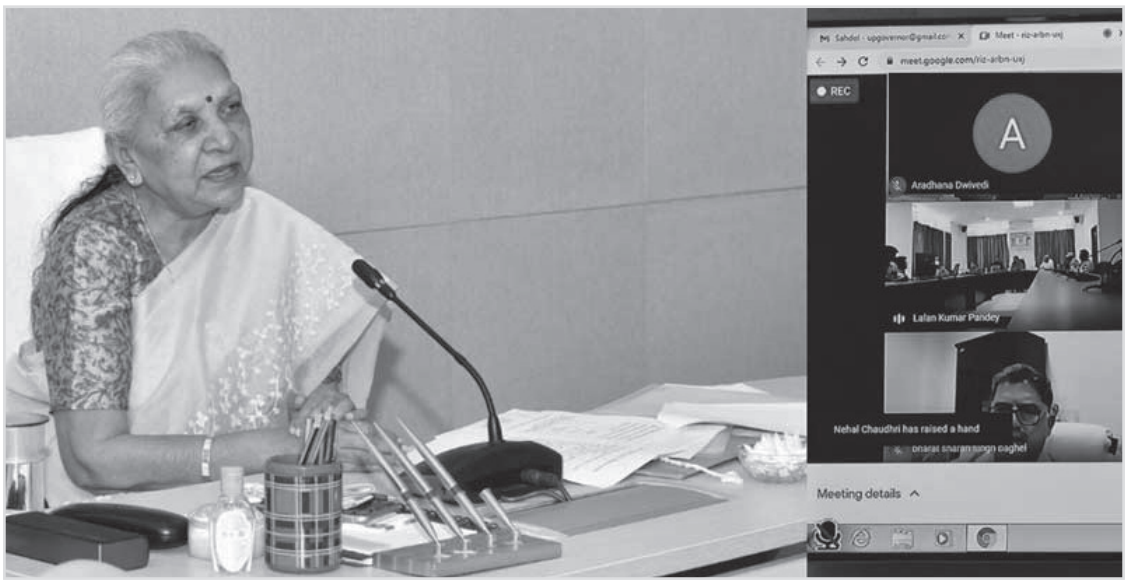

आगामी शिक्षण सत्र की कार्य–योजना बनाएँ

राज्यपाल ने कहा कि महामारी ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक जन–जीवन को प्रभावित किया है। विश्वविद्यालयों के समक्ष आज चुनौती है कि शिक्षा पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को जितना संभव हो, उतना कम किया जाये। आगामी शिक्षण सत्र 2021–22 को ध्यान में रखते हुए आने वाली संभावित चुनौतियों का सामना करने की विस्तृत कार्य–योजना विश्वविद्यालयों को तैयार कर लेना चाहिए। छात्रों की सफलता में छात्र–शिक्षक संबंध एवं परस्पर संवाद अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक होता है। अतः आगामी शैक्षणिक सत्र में मिश्रित शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षण के विकल्पों पर विचार करना होगा। इसके लिए समस्त विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षण तकनीक को निरंतर अद्यतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण कुछ छात्र आर्थिक या पारिवारिक चुनौतियों का सामना कर रहे होगें, ऐसे छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक संवेदनशील होकर कार्य–योजना तैयार करनी चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि आर्थिक संकट के कारण कोई भी छात्र शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं हो।

पाठ्यक्रमों की विषय–वस्तु स्थानीय परिवेश के अनुरुप हो

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें मंथन करना होगा कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति से अर्जित ज्ञान और कौशल को विद्यार्थी अपनी रोजमर्रा की परिस्थितियों में अथवा किन्हीं विषम दशाओं जैसे प्राकृतिक आपदा में उपयोग करने में कितना सक्षम बनाता है। विश्वविद्यालयों को पुनरीक्षण करना होगा कि उनके पाठ्यक्रमों में स्थानीय परिवेश एवं आवश्यकताओं के अनुरूप विषय–वस्तु को चिन्हित किया गया है। साथ ही, पाठ्यक्रमों में मौलिक दर्शन एवं जीवन–कौशल को संवर्धित करने की विषय–वस्तु एवं कार्य –योजना निर्धारित है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा सीखा गया प्रामाणिक ज्ञान समाज एवं देश के हित में प्रासंगिक हो तभी शिक्षा की अवधारणा पूर्ण हो सकेगी।

एक्टिव लर्निंग पर जोर दें

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कोविड–19 जैसी महामारी की भावी चुनौतियों को देखते हुए लगातार प्रतिस्पर्धी होती वैश्विक अर्थव्ययवस्था के मुताबिक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को तैयार करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, एजुकेशन और लर्निंग मॉडल पर फोकस करने और एक्टिव लर्निंग पर ज्यादा जोर देने को कहा है। यूनिवर्सिटी को दुनियाभर में विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन के लिए पहचाना जाए। इसके लिए इनोवेशन के साथ रिसर्च पर फोकस करने और विश्वविद्यालय को नॉलेज जनरेशन और प्रसार के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को प्रगति और उन्नति के नए केंद्र बनाने की दिशा में नए अवसरों को तलाशने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।

हेल्पलाइन शुरु करें

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि छात्र कल्याण गतिविधियों को भी नई पहचान दी जाए। परीक्षा मूल्यांकन आदि से संबंधित जानकारियों और शिक्षकों के व्याख्यानों को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ ही सेमिनार, विभिन्न शैक्षणिक अन्य गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में भी ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराई जाए। विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए हेल्प लाइन भी शुरु की जानी चाहिए।

ऑनलाइन शिक्षा को आऊटकम आधारित बनाए

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से अधिक दक्ष होने की आवश्यकता बताई। शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल एवं ऑनलाइन कोर्स मटेरियल तैयार करने के लिए निरंतर कार्यशालाओं का आयोजन करने, ऑनलाइन शिक्षा को आऊटकम आधारित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करने के लिए कहा। यह कार्य क्वालिटी बेंचमार्क बनाकर आनलाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को क्रेडिट ट्रांसफर के लिए विभिन्न स्तरों पर प्लेटफॉर्म बनाए जाने चाहिए, ताकि छात्र ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स और कार्यक्रमों के जरिए अपने लर्निंग स्किल को बढ़ा सके। इनमें ऐसे कोर्सो का चयन किया जाए जो आज के समय में उद्योगों की जरुरत है। पाठ्यक्रम के ऐसे विषयों जिनमें हुनर अथवा प्रैक्टिकल की जरुरत नहीं है, उन सभी विषय क्षेत्रों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था को मजबूती दी जाए, जिन विषयों में क्षमता आधारित हुनर चाहिए, उन विषयों में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से शिक्षण के लिए विषयों को चिन्हित कर कार्य किया जाना चाहिए। इससे दूरस्थ अंचल में रहने वाले छात्र–छात्राओं के शिक्षण में गुणात्मक परिवर्तन किया जाना संभव है।

शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : उच्च शिक्षा मंत्री

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रोजगार परक शिक्षा में ही शिक्षण संस्थाओं की उपादेयता होती है। विश्वविद्यालय द्वारा नए पाठ्यक्रमों का प्रारंभ, इस दिशा में सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों की संरचना स्थानीय मूल्यों और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए। पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, उनमें मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन शिक्षकों का मौलिक दायित्व है। उन्होंने विश्वविद्यालय के नाम में एस.एन. को शंभूनाथ में प्रतिस्थापित करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहडोल विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की भी स्थापना हुई है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह कॉलेज और विश्वविद्यालय अत्यंत नवीनतम संसाधनों से संपन्न हो पूर्ण क्षमता के साथ संचालित हो रहे है। उन्होंने विश्वविद्यालय से जुड़े सभी व्यक्तियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की।

समाज का मनोबल बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण

मुख्य वक्ता अखिल भारतीय महामंत्री भारतीय शिक्षण मण्डल श्री उमाशंकर पचौरी ने कहा कि शिक्षक असाधारण होता है। शिक्षक के कृतित्व विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। शिक्षक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हैं। आवश्यकता है कि वे अपनी क्षमताओं को पहचान लें। उन्होंने कहा कि चुनौती के इस दौर में आवश्यकता, सकारात्मकता का संचार और समाज का मनोबल बढ़ाने की है। इस कार्य में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री भरत शरण सिंह ने विश्वविद्यालय के साथ उनके दीर्घ संबंधों का विवरण देते हुए विश्वविद्यालय के विकास क्रम का स्मरण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर कोविड संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष के लिए किए गए प्रयासों का विवरण दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री मुकेश तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया। विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। नव–निर्मित भवन में उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं की जानकारी दी।

संबल योजना से काटे गए आठ सौ हितग्राहियों के नाम फिर जुड़ेंगे : मंत्री श्री पटेल

मेरा गांव - मेरा तीर्थ अभियान का किया शुभारंभ

भोपाल। शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अधिकतम लोगों को लाभान्वित किया जाना हर हाल में सुनिश्चित करना है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले के खिरकिया विकासखंड के ग्राम पोखरनी में आयोजित शिविर में संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने पोखरनी से ''मेरा गांव – मेरा तीर्थ'' अभियान का शुभारंभ किया। श्री पटेल ने खिरकिया विकासखंड के ८०० संबल हितग्राहियों के नाम फिर से जोड़ने के निर्देश दिए।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जिले के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा गरीब परिवारों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं का आकलन किया गया था। प्राप्त समस्याओं को दूर करने एवं पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर लाभान्वित किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और किसान ग्रामीण कस्बों में रहते हैं उनकी समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता है। गरीबों की सेवा एवं किसानों की सेवा ही परमात्मा की सेवा है इसलिए उन्होंने इस अभियान का नाम ''मेरा गांव – मेरा तीर्थ'' रखा है। इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी सुविधाओं का लाभ गांव में ही उपलब्ध कराया जाएगा। लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी

श्री पटेल ने पोखरनी में आयोजित शिविर में महिला बाल विकास की मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के अंतर्गत दो बच्चों को लाभान्वित किया । इस योजना के तहत इन बच्चों को पाँच हजार रुपये प्रति माह शासन की ओर से दिया जाएगा एवं बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी शासन के द्वारा वहन किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि इन बच्चों के माता–पिता का कोरोना काल के दौरान स्वर्गवास हो गया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के अंतर्गत 4 हितग्राहियों को, संबल योजना के अंतर्गत 2 हितग्राहियों को, वृद्धावस्था पेंशन के 2 हितग्राहियों को, नारी सुरक्षा पेंशन अंतर्गत 2 हितग्राहियों को एवं आयुष्मान कार्ड 6 के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किया गया। ग्राम के 60 हितग्राहियों के नाम प्रधानमंत्री आवास मिशन अंतर्गत आवास प्लस में जोड़े गए एवं 29 हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची का वितरण किया गया।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्राम पोखरनी में गौशाला निर्माण, पोखरनी से खिरकिया, पोखरनी से कॉलधड़ तक सड़क निर्माण एवं ग्राम पोखरनी में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। शिविर में जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 173 बच्चों को पेंशन वितरित

सरकार और समाज को इन बच्चों का दायित्व लेना होगा। कोविड के प्रकोप में प्रभावित हुए बच्चे अपने आप को अकेला नहीं समझें। उनकी पूरी चिंता की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रत्येक बच्चे के लिए 5 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, ऐसे बच्चों और उनके संरक्षक को प्रतिमाह निःशुल्क राशन और पढ़ाई की व्यवस्था की है। समाज भी इस दिशा में आगे आ रहा है। रतलाम में हुई पहल सराहनीय है।

निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। यदि बच्चा नवीं से 12 वीं में निजी स्कूल में पढ़ता है तो साल में एक मुश्त दस हजार रूपये की सहायता दी जायेगी। शासकीय अनुदान प्राप्त कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की व्यवस्था भी की जाएगी। जो बच्चे जेइई मेन्स परीक्षा या इसी प्रकार की अन्य परीक्षा के द्वारा निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाते हैं, उन्हें 1.50 लाख रूपये तक का शुल्क शासन द्वारा प्रदान किया जायेगा। नीट परीक्षा से प्रवेश पर शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों का पूरा शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। कामन लॉ एडमीशन टेस्ट के द्वारा या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में या दिल्ली विश्वविद्यालय में 12वीं कक्षा के बाद होने वाले एडमीशन में कॉलेजों का समस्त शुल्क राज्य सरकार देगी। पढ़ाई के लिए लेपटॉप या टेबलेट की आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था भी की जाएगी।

अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जायेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेटियों की शादी के समय सहायता के संबंध में भी राज्य सरकार विचार करेगी। इसके साथ ही प्रभावित बच्चों को राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जायेगा।

बच्चों को केन्द्र की कारपस फंड योजना का लाभ भी मिलेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 7वाँ वर्ष पूर्ण हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। वे हमारी प्ररेणा हैं। उनके द्वारा इन बच्चों के लिए आरंभ की गई योजना में 10 लाख रूपये कारपस फंड की व्यवस्था है। यह सहायता भी बच्चों को प्राप्त होगी। अतः बच्चों को चिंता की जरूरत नहीं है। वे मेहनत करें, आगे बढ़ें और संकट को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद सदैव साथ है।

कोरोना अनुकूल व्यवहार बनाये रखें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। कल 78 हजार से अधिक टेस्ट हुए जिनमें से 14 हजार 500 पॉजिटिव आये हैं। 5 हजार से अधिक व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 1.8 प्रतिशत और रिकवरी रेट 95.5 प्रतिशत हो गया है। डिंडोरी, आगर–मालवा और भिंड में कल एक भी केस नहीं आया। अब प्रदेश में धीर–धीरे अनलॉक की प्रकिया आरंभ होगी। परंतु हमें लगातार सावधानी बरतनी है। वायरस अभी हमारे बीच है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमें पुनः संकट में ला सकती है। अतः हमें लगातार कोरोना अनुकूल व्यवहार बनाये रखना है।

अन्य अभिभाव विहीन बच्चों की पहचान की जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि कोविड के अतिरिक्त अन्य कारणों से माता–पिता या अभिभावक विहीन बच्चों की पहचान की जाए। ऐसे बच्चों को भटकने या गलत हाथों में पड़ने नहीं दिया जायेगा। इन बच्चों की सूची बनाकर उनके रहने, अवास और पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया बच्चों से संवाद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना से जुड़े 18 वर्ष से अधिक आयु के कुछ बच्चों से वर्चुअली बात की। इनमें भोपाल के श्री दर्पण सोनी, श्री जयंत पठारिया, रतलाम की श्री पल्लवी सोनी, ग्वालियर के श्री धर्मेंद्र आर्य,कुमारी काजल राजे, निवाड़ी के श्री ध्रुव पस्तोर तथा कुमारी नैना पस्तोर शामिल हैं। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों सतना की श्रीमती गीता चौरसिया, श्री गोरे लाल त्रिपाठी, टीकमगढ़ के श्री अय्यूब खान, श्री राजेश जैन, तथा श्री ब्रजेश अहिरवार, जबलपुर के श्री कैलाश सोनी व श्री देवेन्द्र नायडू, बुरहानपुर के श्री शफीक रहमान तथा श्री प्रवीण बारेला से भी चर्चा की।

मगरधा में 45 लाख की खेत सड़क का किया भूमिपूजन

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों के खेतों तक पहुंचने के लिए खेत सड़क योजना अंतर्गत ग्रेवल सड़कों का निर्माण कार्य कराएंगे। उन्होंने रविवार को हरदा के ग्राम मगरधा में 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाली खेत सड़क का भूमि पूजन किया। मंत्री श्री पटेल ने ग्राम मगरधा में प्रेम नारायण राय के खेत से शिवराम गोर के खेत तक बनने वाली 3 किलोमीटर खेत सड़क का भूमि पूजन करते हुए कहा कि इसके बन जाने से लगभग 70 किसानों को अपने खेतों में पहुंचने के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि वह ग्राम पंचायत मगरधा के कच्चे रास्तों पर किसानों के खेत तक पहुंचने के लिए खेत सड़क योजना के माध्यम से ग्रेवल सड़क का निर्माण कराएंगे।

स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी

अन्य राज्यों को मध्यप्रदेश की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव ● सर्वे पूर्ण कर अधिकार अभिलेखों का वितरण प्रारंभ करें ● मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वामित्व योजना की समीक्षा की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण आबादी का सर्वे कर ग्रामीणों को उनकी स्थिति का मालिकाना हक दिलवाए जाने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख तैयार करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। योजना में अभी तक प्रदेश के 1615 गाँवों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं। हरदा जिले के शत–प्रतिशत गाँवों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं। अधिकार अभिलेख पूर्ण ग्रामों का प्रतिशत 41 है।

भारत सरकार द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस के तहत अन्य राज्यों को भी मध्यप्रदेश की तर्ज पर स्वामित्व अभियान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया गया है। मध्यप्रदेश की प्रक्रिया को समझने अन्य राज्य के अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश का दौरा किया गया, वहीं वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्हें प्रशिक्षण दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना के अंतर्गत सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर ग्रामीण आबादी को अधिकार अभिलेख का वितरण प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, वी.सी. से शामिल हुए। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी आदि उपस्थित थे।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को अपनी सम्पत्ति पर अधिकार का शासकीय दस्तावेज स्वामित्व कार्ड के रूप में दिया जाएगा। इस दस्तावेज के माध्यम से वे अपनी सम्पत्ति का क्रय–विक्रय कर सकेंगे तथा बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

25 सितम्बर 2018 पात्रता तिथि

योजना के अंतर्गत ड्रोन द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर केवल उन सम्पत्ति धारकों के अधिकार अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं जो मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) के लागू होने की दिनांक 25 सितम्बर 2018 को उस आबादी भूमि का उपयोग कर रहे थे अथवा जिन्हें इस दिनांक के बाद आबादी भूमि भूखंड का आवंटन किया गया है।

खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने वेब पोर्टल का शुभारंभ

उत्पादन, भंडारण और प्र-संस्करण की संयुक्त इकाई के लिये मिलेगी प्राथमिकता : राज्य मंत्री श्री कुशवाह

भोपाल। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि उद्यानिकी से जुड़ी उत्पादन, भंडारण और प्र–संस्करण की संयुक्त इकाई लगाने वालों को खाद्य प्र–संस्करण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने निवास स्थित कार्यालय पर विभागीय वेबसाइट <www.mphorticultre.gov.in> के माध्यम से <https://mpfsts-mp-gov-in/mphd/#/> पोर्टल का शुभारंभ किया।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि वर्ष 2018–19 में खाद्य प्र–संस्करण की राज्य योजना मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 में खाद्य प्र–संस्करण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिये संचालित पोर्टल को बंद कर दिया गया था, जिसे आज से पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदेश की उपज को प्र–संस्कृत किये जाने के क्षेत्र में उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में कच्चे उत्पाद को प्र–संस्कृत करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि उत्पादन से जुड़े कृषक और उद्यमी उत्पादन, भंडारण और प्र–संस्करण की इकाई को संयुक्त रूप से स्थापित करेंगे, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 के क्रम में खाद्य प्र–संस्करण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता में लागत पूंजी अनुदान सहायता 35 प्रतिशत और अधिकतम राशि 2.5 करोड़ रूपये देय है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना केन्द्र प्रवर्तित में अधिकतम राशि 10 लाख रूपये अनुदान देने का प्रावधान है।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि राज्य और केन्द्र के द्वारा संचालित खाद्य प्र–संस्करण को बढ़ावा देने की योजनाओं में 600 से 750 करोड़ रूपये का नवीन निवेश होना अनुमानित है। इसके माध्यम से 30 से 40 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी होगा। उन्होंने कहा कि खाद्य प्र–संस्करण योजनाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकीकृत बागबानी विकास मिशन एवं शीतगृह भंडारण में भी उद्यानिकी कृषकों और उद्यमियों को आकर्षक अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इससे उद्यानिकी कृषकों को बढ़ावा मिलेगा। पोर्टल के लोकार्पण के अवसर पर उद्यानिकी आयुक्त श्री एम.के. अग्रवाल भी उपस्थित थे।

सहकारिता में सोशल मीडिया के महत्व पर वेबीनार

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा सहकारिता में सोशल मिडिया के महत्व पर एक वेबीनार का आयोजन किया गया। वेबीनार का उद्देश्य सोशल मिडिया के महत्व पर जागरूक करना था।

श्री दिलीप संघानी, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा कहा गया कि कई सहकारी संगठनों ने सोशल मिडिया के क्षेत्र में प्रवेश किया है लेकिन निजी संगठनों की तुलना में सहकारी संगठनों में सोशल मिडिया के प्रति जागरूकता बहुत कम है यदि सहकारी समितियों को बाजार, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करनी हो तो उन्हे अपने संचार को मजबूत करना होगा, जिसमें सोशल मिडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सहकारी समितियों को स्वयं एवं किसानो की सफलता की कहानियों को सोशल मिडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुंचाना चाहिए।

डॉ सुधीर महाजन, मुख्य कार्यकारी, ने कहा कि किसी संगठन की उपलब्धियों को बताने के लिए सोशल मिडिया को एक सक्रिय मंच के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि वे रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा मिल सकें। जो संगठन सोशल मिडिया पर सक्रिय नहीं है लेकिन स्थानीय स्तर पर अच्छा कार्य कर रहे हैं और स्थानीय मिडिया पर निर्भर हैं, उन्हें मिडिया के इस रूप को अपनाना चाहिए ताकि विश्व स्तर पर सूचनाओं का तुरंत प्रचार–प्रसार हो सके। उन्होने एक स्थायी मॉडल विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां सोशल मिडिया पर अधिक से अधिक सूचनाओं का अदान–प्रदान हो ताकि सहकारी आंदोलन को मजबूत किया जा सके। श्री एस.पी.सिंह, राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख दैनिक जागरण ने कहा कि सोशल मिडिया सहकारिता के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन इसका संतुलित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय संघ को एक सोशल मिडिया सेल बनाना चाहिए ताकि सभी सहकारी संगठनों को एक मंच के माध्यम से जोड़ा जा सके। उन्होने सभी सहकारी बैंकों को ऑन–लाइन बैंकिग अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि सहकारी बैंक अपने सोशल मिडिया प्लेटफार्म को मजबूत करें ताकि उनकी जानकारी तुरंत सभी तक पहुंचे और इस मामले में वे वाणिज्यिक बैंकों से पीछे नहीं रहें। श्री जयन मेहता, सीनियर जीएम, योजना और प्रशासन, अमूल ने कहा कि ''विज्ञापनदाता न बनें, ग्राहक के साथ बातचीत करने के लिए एक सामग्री निर्माता बनें।'' बिना पैसे खर्च किए, सोशल मिडिया की ताकत से हम डार्क चॉकलेट के नंबर 1 ब्रांड बन गए हैं। सोशल मिडिया के अभिनव उपयोग से लॉकडाउन के दौरान अमूल ने अपने सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर लाइव रेसिपी शो आयोजित करने का प्रयोग किया, जो अंग्रेजी, हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित 2500 से अधिक लाइव सत्रों के साथ एक बड़ा हिट बन गया है।

श्री श्रेयस नागरकर, सहायक महाप्रबंधक, विज्ञापन, गठबंधन, कॉर्पोरेट संचार, सारस्वत सहकारी बैंक ने इस अवसर पर कहा कि सोशल मिडिया लोगों के लिए है और हमें लोगों की अपनी भाषा के आधार पर लोगों के संपर्क विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए हमनें इसी सोच के आधार पर अपने सोशल मिडिया प्लेटफार्म को विकसित करना शुरू किया। सारस्वत सहकारी बैंक के सोशल मिडिया पोस्ट केवल बैंकिंग जानकारी से संबंधित नहीं है, बल्कि करंट अफेयर्स के कवरेज, सीएसआर गतिविधियों, घटनाओं आदि की रिपोर्टिंग के साथ व्यापक विकल्प हैं। सारस्वत सहकारी बैंक बैंकिग के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करने वाला पहला बैंक है।

अटल प्रोग्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे के निर्माण प्रदेश की प्रगति को नए आयाम देंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान

अटल प्रोग्रेस-वे उत्तर भारत के उद्योगों को करेगा आकर्षित ● मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की नर्मदा एक्सप्रेस-वे तथा अटल प्रोग्रेस-वे की प्रगति की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के लगभग 17 जिलों से निकलने वाले नर्मदा एक्सप्रेस–वे और ग्वालियर–चंबल संभाग में विकसित होने वाले अटल प्रोग्रेस–वे के कार्य को युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जाए। प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा नए नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए यह दोनों परियोजनाएँ दूरगामी निवेश हैं। यह परियोजनाएँ प्रदेश की प्रगति को नए आयाम देंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में नर्मदा एक्सप्रेस–वे और अटल प्रोगेस–वे की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव वर्चुअली सम्मिलित हुए। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ला तथा श्री नीरज मंडलोई तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अधिक से अधिक शासकीय भूमि का उपयोग हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दोनों ही परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को तेजी से पूर्ण किया जाए। प्रयास यह हो कि परियोजना निर्माण में अधिक से अधिक शासकीय भूमि का उपयोग हो। निजी भूमि अधिग्रहण में भूमि के बदले भूमि देने के विकल्प पर प्राथमिकता से कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अटल प्रोगेस–वे के निर्माण में घड़ियाल अभयारण्य को सुरक्षित रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दोनों परियोजनाएँ शीघ्र पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के स्तर पर वे संबंधित मंत्रियों से संवाद करेंगे।

उत्तर भारत में बन रही परिस्थितियों के कारण ग्वालियर–चंबल का औद्योगिक पोटेंशियल बढ़ रहा है। अटल प्रोग्रेस–वे भिंड, मुरैना तथा श्योपुर जिले से गुजरेगा। यह क्षेत्र दिल्ली–मुम्बई एक्सप्रेस–वे, ईस्ट–वेस्ट कॉरीडोर, आगरा–कानपुर हाइवे के मध्य स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह क्षेत्र उत्कृष्ट औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। दिल्ली तथा आसपास के राज्यों में बन रही परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र का औद्योगिक पोटेंशियल बढ़ रहा है। भिंड में लॉजिस्टिक हब, मुरैना में मल्टी प्रोडेक्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने और श्योपुर में कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की योजना है।

6 हजार 742 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा अटल प्रोग्रेस–वे

अटल प्रोग्रेस–वे की अनुमानित लागत 6 हजार 742 करोड़ रुपये है। कुल 312 किलोमीटर लम्बा यह मार्ग श्योपुर, भिंड और मुरैना के 153 गाँव से गुजरेगा। इस परियोजना के लिए 3 हजार 55 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। परियोजना के अंतर्गत 7 पुल और दो आर.ओ.बी. का निर्माण प्रस्तावित है।

नर्मदा एक्सप्रेस–वे प्रदेश की हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्रियल बेकबोन सिद्ध होगा

नर्मदा एक्सप्रेस–वे प्रदेश को पूर्वी सीमा में एन एच–45 ई बिलासपुर– रायपुर– विशाखापट्नम मार्ग और पश्चिम में गुजरात को जोड़ेगा। लगभग एक हजार किलोमीटर लम्बाई के इस मार्ग के निर्माण पर 2 हजार 696 करोड़ रूपये की लागत अनुमानित है। नर्मदा एक्सप्रेस–वे पूर्वी मध्यप्रदेश को औद्योगिक रूप से उन्नत पश्चिमी मध्यप्रदेश से जोड़कर औद्योकीकरण के नए अवसर पैदा करेगा। यह प्रदेश की हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्रियल बेकबोन सिद्ध होगा। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक इकोसिस्टम का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा इसी बेल्ट में स्थित है। नर्मदा एक्सप्रेस–वे प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला मार्गों, राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेश से विकसित किया जा रहा है।

नर्मदा एक्सप्रेस–वे क्षेत्र में इटारसी और कीरतपुर को लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउस के हब के रूप में विकसित करने की योजना है। मोहासा–बाबई में फार्मा और मल्टी प्रोडक्ट पर केन्द्रित विश्व–स्तरीय पार्क विकसित करने का कार्य जारी है।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क खाद्य सामग्री की वितरित

भोपाल। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की। उन्होंने ग्राम उद्गंवा, नूनवाहा, जौहरिया, गढ़ी, डोंगरपुर और बनौली में 700 से अधिक गरीब और जरुरतमंद परिवारों को नि:शुल्क खाद्य सामग्री के किट वितरित किए।

डॉ.मिश्रा कोरोना के संकट काल में नियमित रूप से दतिया जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद जनता को खाद्य सामग्री के नि:शुल्क किट वितरित कर रहे हैं। जिले के प्रवास के दौरान उन्होंने रविवार को ग्राम उद्गवां में 160, ग्राम नुनवाहा में 300 और ग्राम जौहरिया में 150, एवं ग्राम गढ़ी, डोंगरपुर और ग्राम बनौली में भी जरूरतमंदों को खाद्यान सामग्री प्रदान की। खाद्यान किट में गेंहूँ चावल, दाल, शक्कर, चाय पत्ती, सब्जी, मसाले, मास्क, सेनेटाईज सहित अन्य दैनिक जरूरत की वस्तुएँ शामिल है।

गृह मंत्री डॉ.मिश्रा ने लोगों से कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का उपयोग करने, सेनेटाईज करने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने की समझाईश दी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण केन्द्रों पर जाकर टीका भी अवश्य करायें। इस अवसर स्थानीय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

नव उद्यमियों के उत्पादों को बाजार और पहचान उपलब्ध कराए लघु उद्योग निगम : मंत्री श्री सखलेचा

भोपाल। सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा है कि लघु उद्योग निगम अब एमएसएमई में भूमि आवंटन और निवेश तथा विकास के लिए लागू की गई नवीन नीति से खुद को जोड़कर नव उद्यमियों को छोटे उद्योग लगाने में अपनी भूमिका निभाए। श्री सखलेचा बुधवार को लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों की औपचारिक बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री सखलेचा ने अधिकारियों से कहा कि नई नीति में नव उद्यमियों को अविकसित भूखंड रियायती दर पर मिलेंगे और नाम मात्र की फीस पर वे अपने विकास कार्य कर पाएंगे, जिससे उन्हें अपने सीमित संसाधनों में उत्पादन प्रारंभ करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग निगम अपनी कार्यशैली में बदलाव लाकर छोटी इकाइयां लगाने वाले नए उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकता है।

मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि चाइना के कई उत्पाद आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गायब हैं। उन्होंने कहा कि खिलौना, फर्नीचर जैसे कई उत्पाद हैं जो मध्यप्रदेश में उत्पादित होंगे और सरकार के प्रयासों से इनका एक वर्ष में भारी मात्रा में उत्पादन प्रारंभ होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कच्चा माल और प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों से यह उत्पाद चीनी सामानों की लागत से कुछ कम पर मध्यप्रदेश के बाजारों में धूम मचाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में इन उद्यमों ने कलस्टर के रूप में उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश शंकर मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।